



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]
No. 99]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, जून 19, 2003/ज्येष्ठ 29, 1925
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2003/JYAISTHA 29, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 16 जून, 2003

सं. टीएएमपी/17/2003-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, धूलभरे कार्गो के ढेरों पर जल छिड़काव के लिए प्रशुल्क निर्धारण हेतु विशाखापट्टणम पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/17/2003-वीपीटी

विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी)

आवेदक

आदेश

(जून, 2003 के 5वें दिन पारित)

यह प्रकरण धूलभरे कार्गो के ढेरों पर जल छिड़काव के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने हेतु विशाखापट्टणम पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1 वीपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें कही हैं :-

- (i) यह मुख्य रूप से थोक कार्गो प्रहस्तन करने वाला पत्तन है और लगभग 85% शुष्क कार्गो धूलभरा होता है। अधिकतर वस्तुएँ अर्ध-यांत्रिक साधनों द्वारा प्रहस्तित की जाती हैं, जिसमें जलयानों से कार्गो उतारे जाते हैं और लारियों द्वारा ढेर वाले क्षेत्रों और ढेर वाले क्षेत्रों से जलयानों को भेज दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न स्थानों पर धूल पैदा होती है।

- (ii) आईएसओ 14001 की अपेक्षाओं के अनुपालन में, इसने प्रचालन क्षेत्रों में और उनके चारों ओर 2,30,000 नए पेड़ लगाना, ऐसे कार्गो का प्रहस्तन करने वाले व्यापार जगत की सहायता से मल व्ययन संयंत्र द्वारा साफ किया गया जल धूल भरे कार्गो पर छिड़कने के लिए उपयोग करना जैसे विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए हैं।
- (iii) ऐसे धूलिपूर्ण कार्गो का प्रहस्तन करने वाले विभिन्न पत्तन उपयोगकर्ताओं से अपने-अपने धूल पैदा करने वाले स्थलों/स्थानों पर निरन्तर जल छिड़काव करने का अनुरोध किया गया था। विभिन्न पत्तन उपयोगकर्ता जल वाहक टैंक ट्रकों का प्रयोग कर ऐसा कर रहे थे। पत्तन उपयोगकर्ता का अपने मल व्ययन संयंत्र से पैदा होने वाले जल, पम्पों और निःशुल्क बिजली की आपूर्ति किया करता था। फिर भी, चूंकि यह पम्पिंग ठेकेदार के माध्यम से की जाती है, तो इस कार्य के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रभार वीपीटी द्वारा तत्संबंधी पत्तन उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए थे।
- (iv) इसने अब धूल दबाने हेतु अधिक परिष्कृत और उन्नत प्रणाली पाने के लिए 7.18 करोड़ रुपए की लागत से अभियांत्रिक धूल दबाने वाली प्रणाली कार्यरत की है। यह प्रणाली, पश्चिमी अयस्क बर्थ डेर क्षेत्रों, जी.सी.बी. डेर क्षेत्रों और एस-4 हस्तान्तरक पट्टियों के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों जैसे डेर क्षेत्रों को कवर करती है। इस प्रणाली में कुल 962 छिड़काव यंत्र लगाए गए हैं।
- (v) जैसाकि मै. मेकोन्स लिमिटेड को पांच वर्ष की अवधि के लिए 68.33 लाख रुपए में ठेका दिया गया है और अनुमानित बिजली प्रभार 51.23 लाख रुपए प्रतिवर्ष होंगे। इसकी एक वर्ष की प्रचालन और अनुसंधान लागत 13.67 लाख रुपए आती है। इस प्रकार, प्रत्यक्ष प्रचालन लागत 64.90 लाख रुपए प्रतिवर्ष (13.67 लाख रुपए + 51.23 लाख रुपए) पड़ती है।
- (vi) इसने अब, कम से कम उपर्युक्त प्रणाली पर आने वाली प्रत्यक्ष प्रचालन लागत को वसूल करने का निर्णय लिया है। इसने यह भी बताया है कि अबतक विभिन्न उपयोगकर्ताओं को अपनी लागत पर अपने टैंक ट्रकों में जल का परिवहन कर विभिन्न अपेक्षित स्थलों पर ले जाना पड़ता है। इस नई अभियांत्रिक प्रणाली के आ जाने से, विभिन्न उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाली यह विशेष लागत कम हो जाती है।
- (vii) कम से कम प्रत्यक्ष प्रचालन लागत वसूल करने की आवश्यकता के बारे में व्यापार-जगत को स्पष्ट किया गया था। इसने अभियांत्रिक छिड़काव प्रणाली के अधीन शामिल डेर क्षेत्रों का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं से 80 पैसे प्रति मीट्रिक टन कार्गो की दर से जल छिड़काव प्रभार वसूली करने का निर्णय लिया है।

2.2 वीपीटी ने इस अभियांत्रिक छिड़काव प्रणाली के अधीन शामिल डेर क्षेत्रों का उपयोग करने वाले सभी कार्गो/उपयोगकर्ताओं पर 1 मार्च, 003 से 80 पैसे प्रति टन प्रभार वसूल करने के लिए इस प्राधिकरण से अनुमोदन मांगा है।

3.1 निर्धारित परामर्श प्रक्रियानुसार, वीपीटी का यह प्रस्ताव संबंधित उपयोगकर्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था।

3.2 उपर्युक्त उपयोगकर्ताओं से प्राप्त टिप्पणियों की प्रति वीपीटी को फीडबैक सूचना के रूप में भेजी गई थी।

3.3 इस मामले की संयुक्त सुनवाई 8 मई, 2003 को वीपीटी परिसर में हुई थी। इस संयुक्त सुनवाई में, वीपीटी और संबंधित उपयोगकर्ताओं ने अपने पक्ष प्रस्तुत किए।

3.4 इस संयुक्त सुनवाई में, वीपीटी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए सिद्धांत 'प्रदूषण फैलाने वालों द्वारा भुगतान' दर्शाने वाले दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत की है।

3.5 वीपीटी ने कुछ और लिखित निवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिनका सार निम्नलिखित है :-

- (i) इसने 29 जनवरी, 2003 को हुए विचार-विमर्श के दौरान उपयोगकर्ताओं के साथ हुए मतैक्य के अनुसार प्रस्तावित दर को 1 फरवरी, 2003 से लागू किया है।

- (ii) इसने यह भी बताया है कि जब शारीरिक श्रम वाली छिड़काव प्रणाली प्रचलन में थी तब बिजली की खपत पर व्यय 1.87 लाख रुपए प्रतिवर्ष था।

3.6 तत्पश्चात, वीपीटी ने बताया है कि छिड़काव प्रणाली शुरू करने से लगभग 100 ट्रक प्रतिदिन की आवाजाही में कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप वाहनों से निकलने वाले धुएँ के प्रदूषण में और ट्रकों की आवाजाही में कमी होने से उनके कारण उठने वाली धूल में कमी आई है।

4. इस प्रकरण में हुए परामर्श संबंधी प्रक्रियाएँ इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों के अंश और संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए तर्क संगत पक्षों को अलग से भेजे जाएंगे। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट www.tariffauthority.org पर भी उपलब्ध हैं।

5. इस प्रकरण पर कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :-

- (i) इस छिड़काव प्रणाली की शुरुआत विशाखापट्टनम पत्तन में प्रहस्तन किए जाने वाले धूलभरे कार्गो से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए की गई है। प्रभावशाली, यह नई प्रणाली प्रभावी रूप से न केवल धूलभरे कार्गो से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करेगी, अपितु वाहनों से पैदा होने वाले प्रदूषण को भी कम करेगी क्योंकि जल छिड़काव के लिए पहले उपयोग किए जा रहे ट्रक इस छिड़काव प्रणाली के शुरू होने के पश्चात बेकार हो जाएंगे। जैसाकि एसएआईएल ने सही उल्लेख किया है, पत्तन द्वारा की गई कार्रवाई की प्रशंसा की जानी चाहिए।
- (ii) वीपीटी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत 'प्रदूषण फैलाने वालों द्वारा भुगतान' का उल्लेख किया है। किसी भी मामले में, उपयोगकर्ता पूर्व प्रणाली में जल छिड़काव के लिए निजी ठेकेदार को भुगतान कर रहे थे, जबकि अब उन्हें पत्तन को भुगतान करना होगा क्योंकि पत्तन यह सेवा प्रदान कर रहा है।
- (iii) टीएनईबी ने इस आधार पर वीपीटी के प्रस्ताव पर आपत्ति की है कि इस पत्तन द्वारा संस्थापित छिड़काव प्रणाली सम्पूर्ण ढेर क्षेत्र को कवर नहीं करती। यह आपत्ति उचित नहीं है क्योंकि वीपीटी ने केवल उसी कार्गो परिमाण पर जल छिड़काव प्रभार वसूल करने का प्रस्ताव किया है जो छिड़काव प्रणाली द्वारा कवर किए गए ढेर क्षेत्रों का उपयोग करते हैं।
- (iv) एसएआईएल और टीएनईबी ने मांग की है कि छिड़काव प्रणाली प्रदान करने और प्रचालित करने की लागत पत्तन द्वारा स्वयं वहन की जाए। जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, संबंधित उपयोगकर्ता पहले ऐसी सेवाएँ निजी ठेकेदार को भुगतान कर प्राप्त कर रहे थे। इसके अलावा, वीपीटी ने अपनी ओर से ऐसे निवेश पर होने वाले प्रतिलाभ को छोड़ने का प्रस्ताव किया है। पत्तन ने यह संस्थापित छिड़काव प्रणाली संबंधी प्रत्यक्ष प्रचालन लागत वसूल करने की इच्छा व्यक्त की है। वीपीटी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता।
- (v) वीपीटी ने बिजली लागत और 8 मी.ट. के अनुमानित यातायात सहित प्रचालन लागत पर विचार कर प्रस्तावित दर तय की है। यह उल्लेखनीय है कि पत्तन ने स्वीकार किया है कि उसने पूर्व प्रचालन प्रणाली में जल की पंपिंग के लिए निःशुल्क बिजली प्रदान की है। इस दावे को कि बिजली की आपूर्ति निःशुल्क की गई थी, इस सीमित अर्थ में देखा जाना चाहिए कि संबंधित उपयोगकर्ताओं को खर्च की गई बिजली की लागत का प्रत्यक्ष रूप में भुगतान नहीं करना पड़ता था। पिछले सामान्य संशोधन के समय वीपीटी के प्रशुल्क निर्धारित करते समय लागताधिक स्वीकार किया गया था। अतः यह मानना उचित होगा कि इस सुविधा के लिए बिजली आपूर्ति करने की लागत को भी समग्र व्यय में शामिल किया गया था और उपरिव्यय के रूप में लिया गया था, जिसका अर्थ है कि इसका बोझ वीपीटी की विभिन्न गतिविधियों के प्रभारों में बांट दिया गया।

चूंकि ऐसी स्थिति में ऐसी प्रशुल्क मदों से इस लागत को अलग करना मुश्किल है, इसलिए छिड़काव प्रणाली के प्रचालन के लिए केवल बिजली की वृद्धिशील लागत पर ही विचार करना उपयुक्त होगा। यदि बिजलीकी वृद्धिशील लागत पर विचार किया जाता है तो प्रत्यक्ष प्रचालन लागत बीपीटी द्वारा अनुमानित 64.90 लाख रुपए के स्थान पर 63.03 लाख रुपए होगी। प्रत्यक्ष प्रचालन लागत वसूल करने के लिए 8 मी.ट. यातायात आधार पर विचार करते हुए, जल छिड़काव की दर 78 पैसे प्रति टन आएगी। यह अपेक्षा करना निरर्थक नहीं होगा कि भविष्य में यातायात आधार बढ़ेगा। इस पहलू को स्वीकार करते हुए, जल छिड़काव प्रभार 75 पैसे प्रति टन निर्धारित किए जा सकते हैं। अब निर्धारित की गई दर की दरमान के अगले सामान्य संशोधन के समय समीक्षा की जा सकती है।

- (vi) बीपीटी ने सूचित किया है कि उसने उपयोगकर्ताओं के साथ चर्चा करने के पश्चात 1 फरवरी, 2003 से प्रस्तावित दर लागू की है और इसीलिए उसने अपने प्रस्ताव को 1 फरवरी, 2003 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमोदित करने का अनुरोध है। यह सही है कि बीपीटी द्वारा सृजित सुविधा 1 फरवरी, 2003 से उपयोग की जा रही है। ऐसी सुविधा का उपयोग करने के लिए वसूल किए गए प्रभारों को 1 फरवरी, 2003 से नियमित करने के लिए, विशेष प्रकरण के रूप में, बीपीटी में जल छिड़काव प्रभार 1 फरवरी, 2003 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमोदित किए जाते हैं। बीपीटी ने 1 फरवरी, 2003 से 80 पैसे प्रति टन की प्रस्तावित दर पर तदर्थ प्रभार वसूल किए थे। चूंकि अंतिम अनुमोदित दर प्रस्तावित दर से कम है, इसलिए बीपीटी को अपने बिल पूर्वव्यापी प्रभाव से समायोजित करने और अब तक की गई अधिक वसूली को वापस करने की सलाह दी जाती है।

6. पारिणामस्वरूप, उपर्युक्त कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण विशाखापट्टणम पत्तन न्यास की अभियांत्रिक छिड़काव प्रणाली के अधीन शामिल ढेर क्षेत्र का उपयोग करने वाले सभी कार्गो/उपयोगकर्ताओं पर 75 पैसे प्रति टन जल छिड़काव प्रभार 1 फरवरी, 2003 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमोदित करता है।

7. बीपीटी को अपने दरमान में इस उपबंध को उपयुक्त ढंग से शामिल करने का निदेश दिया जाता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/III/IV/143/03-असाधारण]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th June, 2003

No. TAMP/17/2003-VPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal from the Visakhapatnam Port Trust for fixation of tariff for sprinkling water on dusty cargo stacks as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports
Case No. TAMP/17/2003-VPT

The Visakhapatnam Port Trust (VPT)

Applicant

ORDER

(Passed on this 5th day of June 2003)

This case relates to a proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for fixation of tariff for sprinkling water on dusty cargo stacks.

2.1. The VPT has made the following points in its proposals:

- (i). It is predominantly a bulk cargo handling port and about 85 % of the dry cargo is dusty in nature. Most of the commodities are handled by semi-mechanised means wherein cargoes are discharged from vessels and transported by lorries to the stacking areas and vice-versa. In this process dust is generated at various locations.
- (ii). In order to comply with ISO 14001 requirements, it has taken various pollution control measures like plantation of 2,30,000 saplings in and around operational areas, to utilize treated water by sewage treatment plant for sprinkling the dusty cargoes with the help of trade handling such cargoes, etc.
- (iii). The various port users, who have been handling such dusty cargoes, were requested to constantly sprinkle water at the respective dust generating points/locations. The respective port users by means of tank trucks carrying water were carrying these out. The port used to supply water generated at its sewage treatment plant, pumps and power at free of cost to the user. However, since the pumping is done through a contractor, the charges paid for the same were collected from the respective port users by the VPT.
- (iv). It has now commissioned a mechanical dust suppression system at a cost of Rs.7.18 crores, to have more sophisticated and advance system for dust suppression. This system covers the staking areas such as west ore berth stacking areas, G.C.B. stacking areas and areas north and south of S-4 conveyor belts. This system deploys a total of 172 numbers of sprinkler.
- (v). The operation and maintenance cost for one year works out to Rs. 13.67 lakhs as a contract has been awarded to M/s. Mecons limited for a period of five years at Rs. 68.33 lakhs and the estimated power charges will be Rs. 51.23 lakhs per annum. Thus, the direct operating cost works out to Rs. 64.90 lakhs per annum (Rs. 13.67 lakhs + Rs. 51.23 lakhs).
- (vi). It has now decided to recover atleast direct operating cost incurred for the above system. It has further stated that hitherto various users are required to transport the water in their own tank trucks at their own cost to the various required points. With the commissioning of the new mechanised system, this particular cost to the various users is reduced.
- (vii). The need to recover at least direct operating cost was explained to the trade. It has been decided to levy a rate of Re. 0.80 per metric tonne of cargo from the users, which utilise the stacking areas covered under the mechanised sprinkling system as water sprinkling charges.

2.2 The VPT has sought approval of this Authority to collect a charge of Re. 0.80 per tonne on all those cargoes/users who utilise the stacking area covered under the mechanised sprinkling system with effect from 1 March 2003.

3.1 In accordance with the consultative procedure prescribed, the VPT proposal was forwarded to the concerned user organisations for their comments.

3.2 A copy of the comments received from the above users were forwarded to the VPT as feedback information.

3.3 A joint hearing in this case was held on 8 May 2003 at the VPT premises. At the joint hearing, the VPT and the concerned users have made their submissions.

3.4 At the joint hearing, the VPT furnished copies of documents showing the principle of 'polluters pay' enunciated by the Supreme Court.

3.5 The VPT has furnished further written submission, which is summarised as follows:

- (i). It had implemented the proposed rate with effect from 1 February 2003 as per the consensus arrived with the users during the deliberation held on 29 January 2003.
- (ii). It has also stated that when the manual sprinkling system was in operation, the expenditure on power consumption was Rs. 1.87 lacs per annum.

3.6 Subsequently, the VPT has stated that due to introduction of sprinkler system, there is a decline of about 100 trucks movement per day. This has resulted in decrease in pollution on account of vehicular emission and dust generation corresponding to the reduction in truck movement.

4. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be available in our website www.tariffauthority.org.

5. With reference to the totality of the information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). Commissioning of the sprinkling system is to contain pollution caused by dusty cargo handled at the Visakhapatnam Port. Effectively, the new system contains not only the air pollution caused by dusty cargo but also reduces pollution on account of vehicular emission since the trucks used to sprinkle water earlier would be redundant after commissioning of the sprinkling system. As has been correctly pointed out by the SAIL, the action taken by the port deserves to be complimented.
- (ii). The VPT has pointed out the principle of 'polluters pay' set out by the Supreme Court. In any case, the users were paying to a private contractor for sprinkling water in the earlier system which they have to pay now to the port since the port is providing the service.
- (iii). The TNEB has objected to the proposal of the VPT on the ground that the sprinkling system installed by the port does not cover the entire stack yard. This objection is not found to be relevant since the VPT has proposed to levy the water sprinkling charge only from the quantum of cargo which utilise the stacking areas covered by the sprinkling system.

- (iv). The SAIL and TNEB have demanded that the cost of providing and operating the sprinkling system should be borne by the port itself. As has been pointed out earlier, the concerned users were availing such services earlier from the private contractor against payment. Further, the VPT has made a substantial investment in the sprinkling system; and, on its part it has proposed to forego the return on such investment. The port has sought to recover the direct operating cost towards the newly installed sprinkling system. The approach adopted by the VPT is not found to be unreasonable.
- (v). The VPT has worked out the proposed rate by considering the operating cost including the electricity cost and an estimated traffic of 8 MT. It is noteworthy that the port has admitted that it provided electricity free of cost for pumping water in the earlier system of operation. The claim that the electricity was supplied free of cost should be seen in the limited sense that the concerned users were not required to pay directly for the cost of electricity consumed. Cost plus model was adopted while fixing the tariff of the VPT at the time of the last general revision. It is, therefore, reasonable to assume that the cost supplying electricity to this facility was also included in the overall expenditure and taken as overhead which means its burden has been spread over the charges of various activities of the VPT. Since segregation of this cost from such tariff items at this stage is difficult, it will be appropriate to consider only the incremental cost of electricity for operating the sprinkling system. If the incremental cost of electricity is considered, the direct operating cost will be Rs 63.03 lacs per annum instead of Rs 64.90 lacs projected by the VPT. Considering the traffic base of 8 MT to recover the direct operating cost, the rate for water sprinkling will work out to 78 p. per tonne. It may not be unrealistic to expect that the traffic base will grow in future. In recognition of this aspect, water sprinkling charges can be pegged at 75 p. per tonne. The rate fixed now can be reviewed at the time of the next general revision of scale of rates.
- (vi). The VPT has intimated that it has implemented the rate proposed by it with effect from 1 February 2003 after discussion with the users and hence requested for an approval of its proposal with retrospective effect from 1 February 2003. It has to be recognised that the facility created by the VPT is being used since 1 February 2003. In order to regularise the charges collected for utilisation of such facility since 1 February 2003, as a special case, the water sprinkling charge at the VPT is approved retrospectively with effect from 1 February 2003. The VPT had recovered ad hoc charges at the proposed rate of 80 p per tonne since 1 February 2003. Since the final rate approved is less than the rate proposed, the VPT is advised to adjust its billing retrospectively and refund the excess collection made so far.

6. In the result, and for the reasons give above, and based on a collective application of mind, this Authority approves water sprinkling charge of 75 paise per tonne on all cargo / users that utilise the stacking area covered under the mechanised sprinkling system of the Visakhapatnam Port Trust with retrospective effect from 1 February 2003.

7. The VPT is directed to incorporate this provision in its Scale of Rates appropriately.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[No. ADVT/III/IV/143/03-Exty.]